Ok"ki % 39(vad % 12 (fnlEcj % 2017(eY; % nl #lk,

सीटू मजदूर

संसद के सामने मजदूरों का महापड़ाव

9 – 11 नवम्बर, 2017

(रिर्पोट पृ० 5)

सीटू अध्यक्ष के हेमलता और महासचिव तपन सेन नई दिल्ली में संसद मार्ग पर, 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व स्वतन्त्र राष्ट्रीय फेडरेशनों द्वारा 9–11 नवम्बर, 2017 तक संयुक्त रूप से आयोजित किये गये मजदूरों के विशाल महापड़ाव को संबोधित करते हुए।

सीटू की राष्ट्रीय सचिव व ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स की महासचिव ए आर सिन्धु अन्तिम दिन महिला योजना कर्मियों की विशाल उपस्थिति में महापड़ाव को संबोधित करते हुए।

शोक संवदेना

कॉमरेड सुकोमल सेन को श्रद्धांजलि

सीटू ने एक शोक संवदेना संदेश में, कोलकाता के एक अस्पताल में लम्बी बीमारी के बाद 22 नवम्बर को हुए कॉमरेड सुकोमल सेन के निधन पर गहरे दुख का इजहार किया। वे 83 वर्ष के थे और अपने पीछे पत्नी और दो बेटों को छोड़ गये है। वे देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन के विराट व्यक्तित्व थे।

कॉमरेड सेन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन (ए आइ एस जी ई एफ) के संस्थापक नेता, 1982–2008 तक उसके महासचिव, अपने निधन तक उसके वरिष्ठ वाइस चेयरमैन तथा उसके मुखपत्र–*एम्पलाइज फोरम*– के तीन दशक तक संस्थापक संपादक थे। वे सीटू के उपाध्यक्ष थे तथा बाद में अपने निधन तक सीटू सचिवमंडल में स्थायी आतंत्रित थे। कॉमरेड सेन ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया और वे 1996–2009 तक डब्ल्यू एफ टी यू की ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल पब्लिक एंड अलाइड सर्विसेज (टी यू आइ– पी एंड ए एस) के महासचिव थे।

वह एक विद्वान लेखक थे और *द वर्किंग क्लास इन इंडिया–हिस्ट्री ऑफ इमरजेंस एंड मूवमेंट* (1830–2000) (जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है।) , *द हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन, इंटरनेशनल वर्किंग क्लास मूवमेंट– डायनामिक्स ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड क्लास कोलाबोरेशन*–डब्ल्यू एफ टी यू की स्थापना 1945 से 2011 तक के इतिहास की रूपरेखा समेत कई पुस्तकों के लेखक थे; तथा भारत व विदेश में कई पत्रिकाओं के लिए नियमित योगदान करते थे।

कॉमरेड सुकोमल सेन ने एक सक्रिय कम्युनिस्ट का जीवन जिया वे अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता पर अडिग रहे। वे दशकों तक सी पी आइ (एम) की केन्द्रीय समिति के सदस्य थे तथा अपने निधन तक उसके पदेन सदस्य थे। उन्होंने 1982–1994 तक राज्य सभा के सदस्य के रूप में मेहनतकशों के हितों को संसद में उठाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभायी थी।

दिवंगत नेता के शरीर को सीटू की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के केन्द्र लाया गया जहाँ ट्रेड यूनियन के बहुत से नेताओं ने उन्हें श्रृद्धांजलि दी। सीटू के राष्ट्रीय केन्द्र की ओर से उसकी सचिव ए आर सिन्धु ने सचिव ऊषा रानी के साथ सीटू का झंडा व पुष्पचक्र चढ़ाया। उनकी इच्छा के अनुसार शरीर को चिकित्सकीय शोध के लिए कलकत्ता मेडिकल कालेज को सौंप दिया गया।

कॉमरेड सुकोमल सेन के निधन से देश ने मजदूर वर्ग के आन्दोलन की एक बड़ी हस्ती, विद्वान, दूरदृष्टा व एक महान शिक्षक को खो दिया है और मौजूदा समय में मजदूर वर्ग के सम्मुख उपस्थित शारीरिक व वैचारिक आक्रमण के मद्देनजर यह एक अपूरणीय क्षति है। सीटू ने अपने केन्द्र बी टी आर भवन पर झंडा झुका दिया तथा उनके सभी साथियों व परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की।

अंर्तराष्ट्रीय ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन से शोक संवेदनाऐं

पी.ए.एम.ई.: ''पी.ए.एम.ई. को डब्ल्यू.एफ.टी.यू. के तहत उसके साथ काम करने का सम्मान हासिल हुआ। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स की 16 वीं कांग्रेस के दौरान हमें एथेंस में उनका स्वागत करने का अवसर मिला।

ग्रीस के वर्गीय ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन पी.ए.एम.ई. की ओर से, हम, उनके साथियों और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना व्यक्त करते हैं।''

टीयूआई: '' अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी संघ के महासचिव और कई वर्षों से डब्ल्यूएफटीयू की टीयूआई पी एण्ड एस के महासचिव, कॉमरेड सुकोमल ने न केवल भारत में बल्कि अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के संघर्षों के आयोजन में लगातार योगदान दिया है। हम उनके परिवार और आल इंडिया राज्य सरकार कर्मचारी संघ के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।''

सीटू मजदूर

lhvkbVh;w dk e[ki=

दिसम्बर 2017

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे एस मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम एल मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस.राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

महापड़ाव 5

मजदूर वर्ग का आहवान
–हेमलता– 7

रैंकिंग के खेल और मजदूरों की मुसीबतें
– के आर श्याम सुंदर व
– राहुल सुरेश सपकाल 12

संसद के सामने बैठी किसान संसद 15

राज्यों से 19

ई.पी.एफ.ओ. के सी.बी.टी. की बैठक 21

यूनतम मजदूरी पर सुप्रीम कोर्ट
ने बार–बार क्या कहा 22

जन एकता मशाल मार्च 24

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 26

सम्पादकीय

लड़ाई को नयी ऊंचाईयां दो

सीटू कार्यकर्ताओं के लिए रणभेरी

dkjikjsV ehfM;k vkj ljdkj u eMh dh jfVx vkj ujæ eknh d jkt dk /k/k d fy, lcl vklku ¼bt v,Q Mbx fctul½ crk;w tku dh [kcjk dk [kc tkj&'kkj l çpkfjr dj d fcxMk eM cuku dh gjpUn dkf'k'k dh g A ;g eknh ljdkj dh ml grk'kk dk çdV djrk g tk mldh uhfr;k d vey d urht e ekuo fodkl lpdkd d gj vkdM e vkb pkrjQk fxjkoV l lkeu vk;h g(cky eR;w nj c<h g] Hk[kejh l ekr gb g] egxkb] cjktxkjh cdkc g;h g o m|kx cn g, g] jktxkjk dk fNuuk c<k g vkj mRiknu] fu;kr] fuo'k bR;kfn e deh vkb gA

vDVcj d vUr vkj uoEcj e g;h nk fojkV dk;okfg;k(30 vDVcj dk tu ,drk tukf/kdkj vknkyu(uoEcj e etnjk d rhu fnolh; egkiMko vkj 2 fnu rd ub fnYyh e lln d lkeu yxh fdlku lln u vku oky fnuk e gku oky l?k"kk dh fn'kk Li"V dj nh gA

;w l?k"k turk d fofHkUu rcdk dh ftnxh ij gk jg geyk] voke dh ,drk dk rkMu oky lkEçnkf;d geyk d f[kykQ vkj vlgefr rFkk fojk/k d ykdrkf=d vf/kdkjk dh fgQktr d fy, gA ;gh lc g tk dæ ljdkj e cB lkEçnkf;d & dkjikjsV lÙkklhuk d geyk d fu'kku ij gA vkxkeh eghuk e dh tku okyh dk;okfg;k d fy, tgk gj rcd dk ,d viuk ,tMk g rk lkFk gh ,d lk>k ,tMk Hkh gA

;w gkykr lhV dk;drkvk ij ftEenkjh Mkyr g fd o eík ij vk/kkfjr vudkud vk;keh dk;okfg;k NMx vkj mudh rhork dk u;h Åpkb ij igpk,xA bu lkjs vknkyuk e lhV dk;drkvk dk e[; Hkfedk fuHkkuh iMxhA

lhV dh lHkh ;fu;uk] QMj'kuk vkj bdkb;k d leLr dk;drkvk dk oDr dh t:jr d fglkc l viuh ,frgkfld ftEenkjh ijh dju d fy; mB [kMk gkuk gkxkA

महापड़ाव: अंतिम यात्रा

महापड़ाव में शामिल हुए तीन पराक्रमी सीटू कार्यकर्ताओं का देहान्त

कॉमरेड मुस्तफा को श्रद्धांजलि

कॉमरेड बचन महापात्रा को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली में आयोजित मजदूरों के महापड़ाव में शामिल होने के वास्ते आते /जाते हुए सीटू के तीन पराक्रमी कार्यकर्ताओं –कर्नाटक के कॉमरेड मुस्तफा, ओडिशा के कॉमरेड बचन महापात्र और महाराष्ट्र के कॉमरेड वेंकटेश, के निधन पर सीटू उनके परिजनों और यूनियनों में उनके साथियों के साथ गहरी शोक संवेदना प्रकट करता है।

कॉमरेड मुस्तफा

11 नवंबर को महापड़ाव में भाग लेने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिल का दौरा पड़ने से कॉमरेड मुस्तफा (35) का निधन होने पर उनकी आखिरी यात्रा, कर्नाटक के बीदर जिले के उनके गांव धनपुर में हुई। वह बीएसएनएल के ठेका मजदूर थे और उसकी सीटू यूनियन के सदस्य थे। बीएसएनएलईयू ने चिकित्सकीय व्यवस्था और पार्थिव शरीर को कर्नाटक के उनके गांव ले जाने का काम किया।

अंतिम संस्कार के बाद, एक शोक सभा में उनके परिवार के सदस्यों, पूरे जिले से आऐ मजदूरों व कार्यकर्ताओं और ट्रेड़ यूनियन नेताओं, जिनमें सीटू की राज्य अध्यक्ष एस. वरालक्ष्मी, बीएसएनएल ठेका मजदूरों के राज्य महासंघ के महासचिव महांतेश, एडवा की राज्य नेता के. एस. लक्ष्मी, सीपीआई (एम) जिला सचिव सागर शंभू और अन्य नेताओं ने भाग लिया। बाद में, सभी नेता कॉमरेड मुस्तफा के घर गए, उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की और उन्हे निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया।

कॉमरेड बचन महापात्रा

दिल्ली में आयोजित मजदूरों के महापड़ाव में भाग लेकर वापस जाते हुए, 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन पर एक रेल दुर्घटना में कॉमरेड बचन महापात्रा का निधन हो गया था। सीटू छत्तीसगढ़ राज्य समिति ने ओडिशा राज्य कमेटी को उनके मृत शरीर को प्राप्त करने और राउरकेला ले जाने में सहायता प्रदान की।

कॉमरेड बचन महापात्र राउरकेला कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन (सीटू) के सचिव और ओडिशा में सीपीआई (एम) के राउरकेला की स्थानीय कमेटी के सदस्य थे। सीटू और सीपीआई (एम) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सीटू के राज्य महासचिव बिष्णु मोहंती सहित सीटू राउरकेला कार्यालय और पार्टी के कार्यालय एकेजी भवन, शक्ति नगर में 14 नवंबर को कॉमरेड बचन महापात्रा को आदरपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

कॉमरेड वेंकटेश

दिल्ली में आयोजित महापड़ाव में भाग लेने के लिए आते समय 9 नवंबर को अहमदनगर में एक दुर्घटना के कारण, सोलापुर में सीटू के एक कार्यकर्ता कॉमरेड वेंकटेश का निधन हो गया। सीटू जिला और महाराष्ट्र की राज्य समिति ने उनके अंतिम संस्कार और शोक सभा में भाग लिया और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की।

महापड़ाव

विभाजनकारी और भ्रमित करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से मजदूरवर्ग व अन्य मेहनतकशों के अधिकारों व आजीविका पर हमला कर रही कारर्पोरेट–साम्प्रदायिक मोदीनीत भाजपा सरकार को चुनौती देते; देशभर से हजारों मजदूरों ने, 9–11 नवम्बर, 2017 के नई दिल्ली के संसद मार्ग के महापड़ाव में शामिल होकर इन हमलों के खिलाफ अपने संधर्ष के संकल्प को मजदूर वर्ग व जनता की एकता के विशाल नजारे के साथ पेश किया। महापड़ाव का यह कार्यक्रम, नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 सितम्बर 2015 व 2016 की दो सफल देशव्यापी हड़तालों के बाद संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक प्रमुख कार्यक्रम था।

मजदूरों की दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व स्वतंत्र फेडरेशनों के आह्वान का उत्साह के साथ प्रत्युत्तर देते हुए मजदूर देश के सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों से, सभी संगठित व असंगठित सैक्टरों व उद्योगों से संसद के सामने हुए मजदूरों के इस अब तक के सबसे बड़े जमावड़े में शामिल हुए। कई सारी असम्बद्ध राज्य फेडरेंशनें व यूनियनें भी महापड़ाव में शामिल थीं। मजदूर, महापड़ाव के तीनों दिन दिल्ली पहुँचते रहे। रेलों के देरी से चलने के कारण तीनों दिन लगातार मजदूरों का महापड़ाव में पहुँचना जारी रहा और कुछ तो दिल्ली पहुँचने पर भी शामिल नहीं हो सके। मजदूर, रेलों के साथ ही सभी तरह के सड़क परिवहन के माध्यम से महापड़ाव में आये। तीसरे दिन, उनकी फेडरेशनों के निर्णयों के अनुसार महिला योजना कर्मियों ने भारी संख्या में महापड़ाव में भाग लिया। मजदूरों की मुख्य माँगों व मुद्दों में 18000 रूपये न्यूनतम वेतन; सभी को पेंशन, समान काम के लिए समान वेतन व नियमितीकरण; न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पारिश्रमिक में वृद्धि; मूल्य वृद्धि पर रोक; बेरोजगारी का समाधान; श्रम कानूनों में संशोधनों का विरोध; सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निजीकरण का विरोध; रक्षा क्षेत्र, रेल, बीमा में प्रत्यक विदेशी निवेश का विरोध तथा साम्प्रदायिक व विभाजनकारी नीतियों की खिलाफत के मुद्दे व मांगें शामिल थीं।

महापड़ाव हर दिन सुबह 10 बजे से शाम तक डाला गया। प्रत्येक दिन तीन सत्रों–पहला व अंतिम सत्र केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेताओं का तथा बीच का सत्र केन्द्रीय फेडरेशन के नेताओं का, में पुलिस बैरीकेड के सामने लगे मंच से नेताओं ने महापड़ाव के सत्रों की अध्यक्षता की और मजदूरों को संबोधित किया। महापड़ाव को संबोधित करने वाले राष्ट्रीय नेताओं में इंटक के अध्यक्ष जी संजीव रेड्डी एटक महासचिव गुरूदास दासगुप्ता एच एम एस महासचिव एस एस सिद्धु, सीटू महासचिव तपन सेन, टी यू सी सी के जी. देवराजन, सेवा की मनाली, एक्टू के राजीव डिमरी, एल पी एफ के एम षणमुगम, यू टी यू सी के अशोक धोष–ए आइ यू टी यू सी के सत्यवान व अन्य शामिल थे। महापड़ाव को संबोधित करने वाले अन्य सीटू नेताओं में राष्ट्रीय सचिव ए आर सिंधु व उषा रानी, हरियाणा राज्य महासचिव जयभगवान, निर्माण मजदूर फेडरेशन के महासचिव देवांजन चक्रवर्ती तथा महाराष्ट्र के राज्य अध्यक्ष डॉ. डी एल कराड शामिल थे।

महापड़ाव की अध्यक्षता करने वाले राष्ट्रीय नेताओं में इंटक के अशोक सिंह, एटक अध्यक्ष रामेन्द्र कुमार, एच एम एस अध्यक्ष राजा श्रीधर, सीटू अध्यक्ष डॉ. के हेमलता, ए आइ यू टी यू सी के आर के शर्मा, टी यू सी सी के नरेन चटर्जी, सेवा की सोनिया, एक्टू की संतोष राय, एल पी एफ के सुब्बारमन तथा यू टी यू सी के शत्रुजीत सिंह व अन्य शामिल थे। अध्यक्षता करने वाले अन्य सीटू नेताओं में राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य–एस वरालक्ष्मी, रधुनाथ सिंह, अनादि साहू, एम साई बाबू व के ओ हबीब तथा मध्यप्रदेश राज्य महासचिव प्रमोद प्रधान तथा बिहार राज्य अध्यक्ष दीपक भट्टाचार्य शामिल थे।

महापड़ाव को संबोधित करने वाले राष्ट्रीय फेडरेशनों के नेताओं में ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के महासचिव राधवव्याध, ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोशिएसन (ए आइ बी ई ए,) ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज फेडरेशन के अतिरिक्त महासचिव व इल्क्ट्रीसिटी एम्पलाईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (ई ई एफ आइ) के सचिव सुभाष लाम्बा, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (ए आइ आर टी डब्लू एफ) के महासचिव के के दिवाकरन, ऑल इंडिया डिफेंस एम्पलाईज फेडरेशन (ए आई डी ई एफ) के महासचिव सी श्रीकुमार व कई अन्य शामिल थे।

महापड़ाव के अंतिम दिन भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में पेश किये गये धोषणापत्र का राष्ट्रीय नेताओं ने समर्थन किया। इनमें अभियान, जिला स्तरीय सत्याग्रह/गिरफ्तारियां, सैक्टोरल हड़तालें तथा केन्द्रीय बजट में मजदूर विरोधी, जन–विरोधी प्रस्तावों के आने के फौरन बाद विरोध कार्यक्रम और मजदूरों की अनिश्चितकालीन आम हड़ताल की तैयारियां करना शामिल हैं। धोषणापत्र को सर्व–सम्मति से पारित किया गया।

मजदूरों के महापड़ाव का घोषणापत्र

मजदूर वर्ग से केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का आह्वान

- **मजदूर विरोधी, जन–विरोधी व राष्ट्र विरोधी नीतियों को बदलो**
- **जनवरी, 2018 के अंतिम सप्ताह में जिला स्तरीय सत्याग्रह**
- **निजीकरण के खिलाफ सेक्टरवार संयुक्त हड़ताल**

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें 9–11 नवम्बर, 2017 तक संसद के पास तीन दिन के अभूतपूर्व संयुक्त महापड़ाव में जबर्दस्त व उत्साही भागेदारी के लिए देश के मजदूरवर्ग को हार्दिक मुबारकबाद देती हैं। महापड़ाव के तीनों दिन पूरे समय विभिन्न राज्यों व संगठनों के मजदूरों ने जिस अनुशासन का परिचय दिया वह महत्वपूर्ण व दर्ज करने लायक था। योजना मजदूरों, फेरीवालों, धरेलू मजदूरों, निमार्ण व अन्य घर आधारित कार्य करने वाले मजदूरों, निर्माण व अन्य घर आधारित कार्य करने वाले मजदूरों सहित महिला मजदूरों की विशाल भागेदारी व युवा मजदूरों की हिस्सेदारी इस महापड़ाव का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था।

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूचे देश से आये लाखों मजदूरों ने केन्द्र की भाजपानीत सरकार की मजदूर विरोधी, जन–विरोधी व राष्ट्र–विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने गुस्से का प्रदर्शन किया। महापड़ाव ने एक बार फिर मजदूरों की एकता को तोड़ने की सांप्रदायिक व विभाजनकारी ताकतों की तिकड़मों को धता बताते हुए संयुक्त संधर्षो को तेज करने की मजदूर वर्ग की लगन का प्रदर्शन किया।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने, मजदूर वर्ग की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार विनाशकारी नीतियों को ही आगे बढ़ाने पर अड़ी भाजपा सरकार की, मजदूरों की खराब स्थिति को नजरंदाज करने के रवैये की कड़ी निंदा की। ऐसी परिस्थिति में, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के सामने भाजपा सरकार की मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी व राष्ट्र विरोधी नीतियों को पलटने के सिवा कोई विकल्प नहीं है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, 8 अगस्त, 2017 के नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए मजदूरों के राष्ट्रीय कनवेंशन की रौशनी में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने देश के समूचे मजदूर वर्ग से हड़ताल सहित एक लम्बे आंदोलन की तैयारी करने का आहवान किया। यदि सरकार अपना रवैया नहीं बदलती तो केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें, देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के रास्ते पर जाने को विवश होंगी। इस बीच संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के अगले चरण के तहत आंदोलनों व कार्यवाहियों का सिलसिला जारी रहेगा। मजदूरों के इस तीन दिवसीय पड़ाव के बाद के कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर आने वाले महीनों में हम निम्नलिखित गतिविधियां करेंगे।

– जनवरी 2018 तक संयुक्त जिला स्तरीय कन्वेंशन पूरे करो;
– जनवरी के अन्तिम सप्ताह में जिला स्तरीय सत्याग्रह; सभी जिलों के लिए एक ही तारीख का निर्णय केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व औद्योगिक फेडरेशनों की राज्य स्तरीय संयुक्त बैठक में किया जायेगा;
– सरकार द्वारा निजीकरण के कदम उठाये जाते ही सैक्टर/ उद्योग स्तर पर संयुक्त हड़ताल;
– केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें बजट पेश किये जाने के बाद बैठक कर आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगी।

इंटक, एटक एच एम एस, सीटू, ए आइ यू टी यू सी, टी यू सी सी, सेवा, एक्टू, एल पी एफ, यू टी यू सी; व स्वतन्त्र फेडरेशनें व एसोशिएसनें

विशाल महापड़ाव का मजदूर वर्ग से आह्वान

मोदी सरकार की राष्ट्र–विरोधी नीतियों को पलटने के लिए संघर्ष तेज करो

–हेमलता–

दिल्ली में संसद के सामने आयोजित हुआ मजदूरों का अभूतपूर्व संयुक्त ट्रेड यूनियन महापड़ाव गत 11 नवम्बर को देश के मजदूर वर्ग से किये गये इस आहवान के साथ संपन्न हुआ कि वह भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार की मजदूर–विरोधी, जन–विरोधी व राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करे।

महापड़ाव का आहवान

इस महापड़ाव में देश भर से और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से जुटे मजदूरों ने गत 8 अगस्त,2017 की राष्ट्रीय कन्वेंशन की रोशनी में, संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेतृत्व के इस सर्वसम्मत आहवान को पूरे उत्साह से अपना समर्थन दिया कि अगर सरकार अपना रास्ता नहीं बदलती है और मजदूर वर्ग की आवाज को नहीं सुनती है तो देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड़ताल की तैयारी करें। इस उद्देश्य के लिए ट्रेड यूनियनों ने आंदोलनों तथा संघर्षों के व्यापक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का फैसला किया है। संघर्ष की ये कार्रवाईयाँ जिला स्तर के संयुक्त कन्वेंशनों से शुरू होंगी जो आगामी वर्ष 2018 के जनवरी महीने के पहले सप्ताह तक पूरे हो जायेंगें। इसके बाद, जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में जिला मुख्यालयों पर संयुक्त सत्याग्रहों तथा गिरफ्तारियों के कार्यक्रम होंगे। किसी राज्य के सभी जिलों में गिरफ्तारियों देने की तारीख ट्रेड यूनियनों के राज्य नेतृत्व की संयुक्त बैठक में तय की जायेगी। यदि केन्द्रीय बजट में किसी मजदूर–विरोधी कदम की धोषणा की जाती है तो उसी दिन पूरे देश में संयुक्त विरोध प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक होगी जिसमें आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला लिया जायेगा।

इन कार्यक्रमों के साथ–साथ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने यह भी तय किया है कि सरकार जब भी निजीकरण का कोई कदम उठायेगी उसी समय संयुक्त उधोग/क्षेत्र की हड़ताल आयोजित की जायेगी। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से संबद्ध योजना कर्मियों की राष्ट्रीय फेडरेशनें अपनी मांगो को लेकर केन्द्रीय बजट पेश किये जाने से पहले हड़ताल करेंगी। इस हड़ताल की तारीख उनकी संयुक्त बैठक में तय की जायेगी।

महत्वपूर्ण पहलू

यह तीन दिवसीय महापड़ाव कई मानों में महत्वपूर्ण था। यह पहली बार था कि दस केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र औद्योगिक फेडरेशनों ने संयुक्त यूनियनों और स्वतंत्र औद्योगिक फेडरेशनों ने संयुक्त रूप से देश की राजधानी में तीन दिन तक लगातार धरना दिया जिसमें हर दिन हजारों मजदूरों ने भाग लिया। महिला मजदूरों, जिनमें केवल योजना कर्मी ही शामिल नहीं थीं, बल्कि बीड़ी, निमार्ण, घरेलू महिला कामगार, फेरी वाली, घर आधारित कार्य करने वाली आदि की महिला मजदूर भी भारी संख्या में शामिल थीं, ने महापड़ाव के तीसरे दिन विशाल तादाद में महापड़ाव में हिस्सा लिया। युवा मजदूरों ने भी महापड़ाव में बढ़–चढ़ कर हिस्सेदारी की।

महापड़ाव का एक अन्य खास पहलू यह रहा कि इसमें अनेक राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया। इनमें से कुछ केरल व तेलंगाना आदि राज्यों में राज्यस्तरीय संयुक्त ट्रेड यूनियन मंचों का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के आहवान पर विभिन्न राज्यों से करीब 30,000 परिवहन मजदूरों और ट्रक मालिकों तथा ड्राइवरों ने भी इस महापड़ाव में भाग लिया, जो किसी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन से संबद्ध नहीं हैं।

मजदूरों ने सभी मुश्किलों को पार करते हुए इस महापड़ाव में शामिल होने के मामले में असाधारण संकल्प का परिचय दिया। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को देश भर में मीडिया ने उठाया था। दिल्ली के 'जहरीली गैस के चेंबर' में बदल जाने और 'सार्वजनिक

स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति बन जाने' ने महापड़ाव में, विशेषकर दक्षिणी राज्यों से आने वालों में एक डर पैंदा कर दिया था। राष्ट्रीय हरित पंचाट द्वारा जंतर–मंतर पर धरनों–प्रदर्शनों पर रोक लगा दिये जाने ने भी यह सवाल पैदा कर दिया था कि महापड़ाव होने दिया जायेगा या नहीं।

बहुत सी रेलगाड़ियां भी देरी से चल रही थीं और कई तो रद्द ही कर दी गयी थीं। ऐसे में, महिला मजदूरों समेत उन हजारों मजदूरों को वापस लौटना पड़ा, जो दूर–दराज से चलकर अपने नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर पहुँचे थे और पहुँचने पर उन्हें पता चला था कि उनकी रेलगाड़ियां रद्द हो गयी हैं। यह मालूम होने पर कि रेल देरी से चल रही हैं हजारों मजदूरों ने वापस लौटने से इन्कार कर दिया। वे कम वक्त के लिए ही सही महापड़ाव में भग लेना चाहते थे। तीनों दिन 'महापड़ाव' स्थल पर लोग तब तक पहुँचते रहे जब यह अगले दिन फिर शुरू होने के लिए खत्म होने वाला होता था। हजारों महिला मजदूर तो 11 नवम्बर की रात को दिल्ली पहुँची थीं।

भ्रमित करने के प्रयास

मजदूरों में भ्रम फैलाने के प्रयास भी किये गये। मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद, 2 सितम्बर, 2015 को हुई पहली संयुक्त देशव्यापी आम हड़ताल की पूर्व संध्या पर, मोदी सरकार को यह प्रमाणपत्र देते हुए कि वह मजदूरों की मांगों के प्रति सकारात्मक है, संयुक्त आंदोलन को छोड़कर भाग खड़ी होने वाली बी एम एस ने 17 नवम्बर को राजधानी में रैली करने का आहवान किया था। ऐसी अफवाहें भी फैलायी गयी थीं कि महापड़ाव को रद्द कर दिया गया है।

सरकार ने, जो, पिछले कोई दो वर्षो से ट्रेड यूनियनों के 12 सूत्री माँगपत्र की पूरी तरह से अनदेखा करती रही, 3 नवम्बर को एक बैठक बुलायी जिसके लिए 48 धंटे से भी कम का नोटिस दिया गया था। लेकिन सरकार ने इस बैठक में इंटक को आमंत्रित नहीं किया था, जो संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन की एक अहम घटक व एक प्रमुख केन्द्रीय ट्रेड यूनियन है। जब ट्रेड यूनियनों ने इसका विरोध किया और इंटक को आमंत्रित नहीं किये जाने पर बैठक में शामिल होने से इन्कार किया तो सरकार ने इस बैठक को रद्द कर दिया और उसी दिन एक और बैठक बुला ली जब अन्य तीन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों को संसद की श्रम संबंधी स्थायी समिति के सामने अपनी बात रखने के लिए मुंबई बुलाया गया था। जब श्रम मंत्रालय के इस गैर–गंभीर रूख को लेकर ट्रेड यूनियनों ने फिर अपना विरोध जताया तो आखिरकार 7 नवम्बर की शाम को यह बैठक रखी गयी। लेकिन सरकार के पास कहने को कुछ नहीं था। ट्रेड यूनियनें अपने कार्यक्रम पर टिकी रहीं।

मजदूरों ने भ्रम पैदा करने, उनकी एकता को छिन्न–भिन्न करने की इन सभी साजिशों की परवाह न करते हुए भारी संख्या में इस महापड़ाव में भाग लिया।

मजदूरों का अनुशासन

तीन दिन के इस महापड़ाव के दौरान विभिन्न राज्यों व संगठनों से संबंधित मजदूरों ने अनुशासन का उदाहरण पेश किया। अधिकतर मजदूर पूरे दिन धरने पर बैठे ध्यान से वक्ताओं को सुनते रहे, जिनकी संख्या हर रोज तीन सत्रों में कम से कम से कम तीस होती थी ! जब भी संधर्ष को तेज करने का आहवान किया जाता वे पूरे उत्साह से उसका समर्थन करते थे।

कॉर्पोरेट मीडिया और सोशल मीडिया

तथापि, कार्पोरेट मीडिया के लिए इस सबका कोई मलतब नहीं था। कार्पोरट नियंत्रित मुख्य धारा के प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया ने इस महापड़ाव तथा अर्थव्यवस्था की रीढ़ का काम करने वाले मजदूरों की मांगो को पूरी तरह से अनदेखा किया। उसने जो दिखाया तो सिर्फ इतना कि कुछ गरीब फेरीवाले जूते व किताबें बेचकर खूब कमा रहे हैं और कि सार्वजनिक शौचालयों के बाहर लम्बी कतारें लगी हुयी हैं!

लेकिन सोशल मीडिया और कुछ जन–हितैषी टी वी चैनलों में इस महापड़ाव और उसके द्वारा उठाये गये मुद्दों को खूब प्रचार मिला। सोशल मीडिया में सक्रिय अनेक टीमों ने मजदूरों व ट्रेड यूनियन नेताओं से की गयी बातचीत को अपनी वेबसाइटों पर डाला।

तपन सेन का निष्कर्ष : संदेश को जनता तक ले जाना है

सीटू के महासचिव तपन ने महापड़ाव के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मजदूर वर्ग, नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में कार्पोरेट मीडिया के समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही नीतियां है जो बड़े घरेलू तथा विदेशी कार्पोरेट धरानों के लाभ के लिए बनी हैं और उन्हीं की शह पर इन्हें लागू किया जा रहा है। उन लाखों मजदूरों को जो सिर्फ देश के शहरों व कस्बों से ही नहीं बल्कि दूर–दराज के कोनों से आये उन्हें महापड़ाव के संदेश को मजदूरों व मेहनतकश जनता के सभी तबकों तक ले जाना है।

विशाल बिरादराना समर्थन व एकजुटता

मजदूरों के इस संधर्ष और उनकी माँगों को देश के भीतर से और बाहर से कितने ही संगठनों का समर्थन मिला। मजदूर वर्ग के दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन (डब्लू एफ टी यू) और इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कंन्फेडरेशन (आइ टी यू सी) ने अपने एकजुटता संदेश भेजे थे। इसके अतिरिक्त यूनान तथा नेपाल आदि समेत विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ट्रेड युनियन संगठनों ने भी एकजुटता प्रकट की। करीब 100 किसान संगठनों के संयुक्त मंच और कई महिला संगठनों ने भी इस महापड़ाव को अपना समर्थन दिया। लेखकों, प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों, शोधार्थियों कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत देश की 50 जानी–मानी हस्तियों ने यह माँग करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि मजदूरों के संयुक्त आंदोलन द्वारा उठाये गये मुद्दों को फौरन संबोधित किया जाये। मजदूरों के संधर्ष के समर्थन में और भी बहुत तरफ से एकजुटता व्यक्त की गयी।

सीटू की भूमिका

इस महापड़ाव में सीटू की उपस्थिति अच्छी खासी और दिखायी तड़ने वाली रही। सीटू केन्द्र व उसकी राज्य समितियों तथा औद्योगिक फेडरेशनों ने प्रभावशाली तैयारियों की थीं। 8 अगस्त, 2017 की संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन के निर्णय के बाद की इस तीन महीने की अवधि में 'जिन तक नहीं पहुँचे हैं उन तक पहुँचने' के उद्देश्य के साथ मजदूरों के बीच सधन अभियान चलाने का कार्य किया गया। संयुक्त पर्चों व पोस्टरों के अतिरिक्त सीटू, समितियों ने स्थानीय भाषाओं में लाखों पुस्तिकायें, पैंफलेटस और परचे प्रकाशित किये थे। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की सीटू की यूनियनों और फेडरेशनों ने इन सेक्टरों के मजदूरों के विशेष मुद्दों पर लाखों की संख्या में परचे व पुस्तिकायें प्रकाशित की थीं। इनमें, केन्द्र में एक के बाद एक आयी सरकारों, फिर वे भाजपा की रही हों या काँग्रेस की, के द्वारा आगे बढ़ायी गयीं नवउदारवादी नीतियों के दुष्परिणामों को विस्तार से सामने रखा गया था। देश भर में जत्थों, आम सभाओं, गेट मीटिंगों, मुहल्ला सभाओं, नुक्कड़ सभायें आदि आयोजित की गयीं जिनमें लाखों की संख्या में मजदूरों की भागेदारी रही।

बढ़ता असंतोष और आगामी कार्य

इस तीन दिवसीय महापड़ाव ने जो एक चीज पूरी तरह स्पष्ट कर दी है वह यह कि मजदूर वर्ग के सभी तबकों में, फिर चाहे वे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों या संगठित क्षेत्र के मजदूर हों, या निजी क्षेत्र के, योजना मजदूर हो या अन्य सभी मजदूर, सभी में सरकार की नीतियों के विरोध में असंतोष बढ़ रहा है। यहाँ तक कि मध्यवर्गीय कर्मचारियों के बड़े हिस्सों का, जिन्होने भाजपा को मत दिया था, सरकार की नीतियों से मोहभंग हो रहा है।

इस महापड़ाव ने यह दिखाया है कि मजदूर लड़ने के लिए तैयार हैं। जरूरत उन्हें विनाशकारी नवउदारवादी नीतियों के विकल्प के बारे में जागरूक करने की है; उन्हें यह बताने की आवश्यकता है कि मजदूर वर्ग ही इस विकल्प के लिए संधर्ष की अगुवाई करेगा। उनमें यह विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है कि मजदूर, ऐसा किसानों व खेतमजदूरों जैसे अन्य मेहनतकश तबकों को साथ लेकर अपनी संगठनात्मक ताकत के बल पर ही कर सकते हैं।

सीटू जैसी वर्ग आधारित ट्रेड यूनियन के लिए आगे का कार्य यही है। महापड़ाव की शानदार सफलता और उसे इतना सफल बनाने में सीटू की भूमिका ने इस कार्य को आगे बढ़ाने और पूरा करने में उसकी जिम्मेदारी को और भी बढ़ा दिया है।

डब्ल्यू.एफ.टी.यू. का एकजुटता संदेश

एथेन्स, 10 नवम्बर 2017

भारत में तीन दिनों की जन कार्यवाही के प्रति डब्ल्यू.एफ.टी.यू. महासचिव का एकजुटता वक्तव्य

वर्गीय ट्रेड़ यूनियन आंदोलन और वर्ल्ड फैड़रेशन ऑफ ट्रेड़ यूनियन्स के 920 लाख मजदूर सदस्यों की ओर से, मैं भारत के मजदूर वर्ग और उसके ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजदूर वर्ग की महान लामबन्दी के लिए हमारी सम्पूर्ण लगन एवं हार्दिक समर्थन के साथ एकजुटता व्यक्त करता हूँ।

भारत के सभी सैक्टरों और क्षेत्रों से 9–11 नवंबर 2017 को तीन दिवसीय प्रदर्शन में भाग लेने आऐ सैकड़ों श्रमिक, मजदूरों की संगठित शक्ति को साबित कर रहे हैं और जुझारु संघर्षों के तरीके को दर्शा रहे हैं। मजदूर वर्ग की चेतनापूर्ण एकता और जुझारु संघर्ष ही मौजूदा आक्रामकता से पार पाने का एकमात्र तरीका है। यह स्थिति पूंजीवादी राज्यों के असमान आर्थिक विकास के कारण पैदा होती है, जो मुनाफे और शोषण के आधार पर विकसित की जाती है।

भारत सरकार और बुर्जुआ वर्ग की मजदूर–विरोधी और नवउदारवादी नीतियों और प्रथाओं के खिलाफ आपके संघर्ष का डब्ल्यू.एफ.टी.यू.पूरा समर्थन करता है। हम न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी, रोजगार के लिए, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा की माँग और श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों और निजीकरण के खिलाफ आपकी माँगों का समर्थन करते हैं। हम मजदूरों, किसानों और आम जनता के हितों के पक्ष में लोकप्रिय स्तर पर, आपकी उचित मांगों की पूर्ण स्वीकृति और लागू कराने के लिए लगातार संघर्षरत भारतीय मजदूरों के पक्ष में खड़े हैं।

डब्ल्यू.एफ.टी.यू. आपके ट्रेड यूनियन आंदोलन के निर्णायक और गर्वपूर्ण उत्तर को सलाम करता है और यह पुष्टि करता है कि पूरे विश्व का मजदूर वर्ग, पूंजीवादी बर्बरता और मानव द्वारा मानव के शोषण के खिलाफ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्गीय ट्रेड़ यूनियन आंदोलन के समर्थन और एकजुटता पर भरोसा कर सकता है।

भारत के मजदूरों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय विरोध के साथ एकजुटता

ग्रीस के वर्गीय ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल वर्कर्स मिलिटेंट फ्रंट–पेम (पी.ए.एम.ई.), 9–11 नवंबर को भारत में तीन दिवसीय लामबन्दी के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करता है।

भारत के मजदूर संसद के सामने तीन दिवसीय लामबन्दी की तैयारी में हैं, नई दिल्ली में जहाँ पूरे देश से आऐ लाखों मजदूर विरोध करेंगे। भारत में डब्ल्यू.एफ.टी.यू. से सम्बद्ध ट्रेड यूनियनों की अगुवाई में पिछले वर्षों के दौरान न्यूनतम वेतन और सभी के लिए पेंशन, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारों के लिए रोजगार आदि जैसी माँगों के लिए भारी लामबन्दियाँ, आम हड़तालें आदि कार्रवाई की जाती रही हैं।

पी.ए.एम.ई. भारतीय कामगारों की इस महान लामबन्दी के साथ अपने समर्थन और एकजुटता को व्यक्त करता है और उनकी उचित माँगों के मान लिए जाने की माँग करता है।

एथेंस, ग्रीस, 9 नवंबर 2017

सीटू का आह्वान
मूल्य वृद्धि के खिलाफ देशव्यापी विरोध दिवस

सीटू ने लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के विरोध में अपनी सभी इकाईयों, फेडरेशनों व यूनियनों से प्रत्येक औद्योगिक केन्द्र, शहर, नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में मेहनतकशों के सभी तबकों को शामिल करते हुए देशव्यापी स्वतन्त्र अभियान छेड़ने का आहवान किया है। इस अभियान का समापन 13 दिसम्बर, 2017 को मूल्य वृद्धि के खिलाफ विरोध दिवस के रूप में प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार के पुतले के दहन के साथ होगा।

सीटू ने 16 नवम्बर को जारी एक बयान में कहा कि सरकार द्वारा फर्जी तरीकों से समय–समय पर मूल्य सूचकांकों में गिरावट के बावजूद; वास्तविकता में, अनाजों, सब्जियों, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं, शिक्षा आदि समेत सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

''मोदी सरकार की नीतियां व असफलतायें मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं।'' मूल्य केवल बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि बिचौलियों, बड़े व्यापारियों, कालाबाजारियों व सट्टेबाजों को लाभ पहुँचाने की सरकार की नीति और 'व्यापार को आसान बनाने के लिए' जो दरअसल 'लोगों को लूटना आसान बनाने' का पर्याय बन गया है के लिए मूल्यों को बढ़ाया जा रहा है। मोदी के शासन में देश की स्थिति 'व्यापार करने की आसानी' के सूचकांक में ऊंची है और ''भूख'' सूचकांक में नीची है।

पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार अन्तराल पर वृद्धि की जा रही है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट या ठहराव के बावजूद रसोई गैस की सब्सिडी में बराबर कटौती की जा रही है जिसका सभी आवश्यक वस्तुओं के दामों पर सीधा असर हो रहा है। नोटबंदी के बाद जी एस टी के लागू किये जाने से मूल्य वृद्धि में और तेजी हुई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जैसे ठप्प ही कर दिया जा रहा है। हर चीज को आधार के साथ जोड़ने समेत विभिन्न शर्तो के थोप दिये जाने से बड़ी संख्याा में गरीब लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों से वंचित हो रहे हैं और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मजाक बन रहा है।

किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। उनकी उपज का दाम, बाजार में अनाज व अन्य कृषि उत्पादों के दामों से कहीं कम मिल रहा हैं। सरकार मनरेगा समेत कल्याणकारी खर्चो पर कटौती कर गरीबों को उचित न्यूनतम वेतन से वंचित कर उनकी मुश्किलों को बड़ा रही है। मनरेगा में पूरे देश में उपलब्ध कार्य दिवसों की घटती संख्या इसकी गवाही देती है।

9.2 करोड़ मनरेगा मजदूरों को नहीं मिला वेतन; केन्द्र जारी नहीं कर रहा पैसा

31 अक्टूबर, 2017 तक 19 राज्यों में मरनेगा के तहत 9.2 करोड़ ग्रामीण मजदूरों को, केन्द्र सरकार द्वारा पैसा जारी नहीं किये जाने के कारण 3,066 करोड़ रूपये का भुबतान नहीं किया गया है। मनरेगा के तहत वेतन का भुगतान 15 दिन के भीतर होना चाहिये। भुगतान में देरी की स्थिति में मजदूरों को मुआवजे का अधिकार है। *(सोशल मीडिया से)*

बिना टिप्पणी

गिरावट

सरकार की 'मेक इन इंडिया' मुहिम मुश्किल में है। इसका उद्देश्य सकल घरेलू उत्पादन में विनिमार्ण के हिस्से को 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 2022 तक 25 प्रतिशत तक करना और 10 करोड़ रोजगार पैदा करना है। लेकिन, मोदी के तीन वर्ष के कार्यकाल में औद्योगिक वृद्धि कमजोर रही है, निवेश की दर गिरी है रोजगार की वृद्धि खस्ताहाल है तथा निर्यात में ठहराव है।'' *(द् इकॉनामिक टाइम्स, 22 नवम्बर, 2017)*

रैंकिंग के खेल और मजदूरों की मुसीबतें

– के आर श्याम सुंदर व राहुल सुरेश सपकाल –

सरकार जब विश्व बैंक की शाबासी अर्जित करने के लिए केवल व्यापार को ही शह देगी तो उसका खामियाजा मजदूरों को उठाना पड़ता है

विश्व बैंक द्वारा 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' (ई डी बी) यानि व्यापार में आसानी के बारे में की गई कवायद में भारत के रैंक में 2016 की 130 वीं स्थिति के मुकाबलें 2017 में 100 वें स्थान पर पहुँचने की उछाल को एक ही साथ खुशी व अविश्वास के रूप में लिया गया है (यह देखते हुए कि अर्थव्यवस्था नोटबंदी व जी एस टी के नकारात्मक असर से उबर रही है) रोजगार वृद्धि लड़खड़ा रही है और टेलिकॉम व आई टी सैक्टरों में कंपनियां मजदूरों को काम से बाहर निकाल रही हैं।

व्यापार की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए जहाँ नौकरशाही पर अंकुश रख इसे शिथिल रखना जरूरी है वहीं अनियन्त्रण के इस तर्क को क्या रोजगार सृजन के नाम पर श्रमिकों तक भी विस्तृत किया जायेगा ? विश्व बैंक को श्रम बाजार के नियन्त्रण मुक्त होने का समर्थन करने के लिए जाना जाता है।

रैंकिंग का राजनीतिक अर्थशास्त्र

रैकिंग की कवायदें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नियामक नीतियों में बदलाव के लिए हित समूह और देश इस खेल में शामिल होने पर गर्व महसूस करते हैं। 2018 की रिपोर्ट मानती है कि 190 देशों में से 119 ने कम से कम एक नियामक सुधार अवश्यक किया ताकि उसे बिजनेस के लिए ज्यादा दोस्ताना माना जा सके। यद्यपि श्रम बाजार के नियन्त्रण को चारों ओर से हुई आलोचना के चलते 2010 से रैंक नहीं किया गया, लेकिन यह विश्व बैंक की नियामक मनोस्थिति में बना हुआ है।

समस्या यह है कि बिजनेस व शासक दल सामाजिक व आर्थिक प्रगति के धटकों पर आधारित रैंकिंग के स्पष्ट अंतर को नजरंदाज करते हैं। भारत को जहाँ बिजनेस की आसानी के मामले में ''विवादास्पद'' अच्छी रेटिंग मिली है, अन्य क्षेत्रों में उसकी हालात बहुत बुरी है। आई एल ओ कि वैश्विक वेतन रिपोर्ट भारत में आय के वितरण की बहुत ही बदतर स्थिति को दिखती है। सबसे अधिक भुगतान पाने वाले सर्वोच्च 10 प्रतिशत आय समूह, सभी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन का 43 प्रतिशत प्राप्त करते हैं, जबकि सबसे कम पाने वाले 50 प्रतिशत आय वाले समूह केवल 17 प्रतिशत प्राप्त करते हैं। डेवलपमेंट फिनान्स इंटरनेशनल व औंक्सफेम की हालिया नीति रिपोर्ट में भारत को सामाजिक खर्च के मामले में 152 देशों में 149 वें स्थान पर, प्रगति शील कराधान के मामले में 91 वें स्थान पर तथा श्रम अधिकारों के मामले में 86 वें स्थान पर रखा गया है। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस कौंसिल द्वारा मापे गये श्रमिक अधिकार सूचकांक (मजदूरों के अधिकारों की कोई गारण्टी नहीं होने का सूचक) में भारत को लगातार तीन वर्षो तक सबसे बुरी रैकिंग दी गयी है।

जहाँ ई डी बी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लधु व मध्यम फर्मो को बिजनेस में नौकरशाही की और से कोई अड़चन न हो, वहीं इसके पास देशों व राज्यों के बीच नियन्त्रण खत्म करने के मामले में नीचे की ओर एक रेस को बढ़ावा देने की शक्ति है। रवांडा जैसे कुड देशों ने अपनी बिजनेस प्रोफाइल की देखरेख के लिए एक नौकरशाही स्थापित की है। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि केन्द्र ने विश्व बैंक के दबाव में एक धरेलू बिजनेस ईज रैकिंग की कवायद शुरू की है।

ईज ऑफ डूईंग बनाम श्रम अधिकार

यह महत्वपूर्ण होने के साथ परेशान करने वाला भी है कि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोमोशन (डी आइ पी पी) ने संबंधित श्रम कानूनों के मामलों को देखने के संबंध में श्रम मंत्रालय को बदल दिया है। डी आइ पी पी ने राज्यों में श्रम बाजार को नियन्त्रण मुक्त करने के लिए विस्तृत ''नियम'' जारी किये हैं। राज्यों के श्रम विभाग ''ईज ऑफ

डुईंग बिजनेस''! के लिए गर्व से लेबर इस्पेक्शनों के उदारीकरण की धोषणा करते हुए आई एल ओ के बजाय विश्व बैंक का उल्लेख कर रहे हैं।

लेकिन, वे मजदूरों को डीम्ड यूनियन पंजीकरण प्रदान करने या मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा लाभों के दावों के मामलों में उनकी मदद करने के लिए नौकरशादी में सुधार करने के प्रति तुलनात्मक रूप से कहीं कम इच्छुक दिखायी देते हैं। खतरे आधारित निरीक्षण, (बिना भरोसेमंद ओकडों के ही) मशीन नियन्त्रित निरीक्षण आदेशों (श्रम निरीक्षकों में ''मरजी'' के हिसाब से किराया वसूल करने वाले तत्वों को हटाने के लिए), तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिटिंग, अधोषित निरीक्षणों की समाप्ति, स्व–प्रमाणीकरण आदि को ''ईज ऑफ डूईंग बिजनेस'' के लिए कई सारे राज्यों द्वारा तैयार किया गया है।

श्रम निरीक्षण व्यवस्था का उदारीकरण कर भारत ने आई एल ओ के लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन (081) का उल्लंधन किया है, जिसका उसने अनुमोदन किया हुआ है– यह कन्वेंशन कहता है कि किसी प्रतिष्ठान का निरीक्षण जल्दी–जल्दी और किसी समय यहाँ तक कि बिना पूर्व सूचना के किया जाना चाहिये।

स्बसे बुरा यह है कि विधायी सुधारों ने अनौपचारिकता को इतना दूर तक बढ़ा दिया है कि फर्म और ठेकेदार कानूनी दायरे से ही बाहर हो गये हैं। दुसरी ओर, और ज्यादा मजदूर लाभों व नियमों के दायरे से बाहर हैं। ईज ऑफ डुईंग बिजनेस के लिए समाज कल्याण की ज्यादा उपयोगिता नहीं है।

(सुंदर एक्स एल आई, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं, सपकाल, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई में आसिसटेंट प्रोफेसर हैं)

मूडी' ने लिफ्ट किया मोदी का मूड

कैंसर पिछले जन्म के पापों का फल : का भाजपा मंत्री का बयान

असम के स्वास्थ्य, शिक्षा व वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में 248 स्कूली शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते एक समारोह में कहा कि, कैंसर व वैसी ही अन्य जानलेवा बीमारियों का कारण पिछले जन्म में किये गये पाप हैं। मंत्री के अनुसार, भारत में जितने भी मरीज कैंसर से पीड़ित हैं वे पिछले जन्म में किये गये पापों का फल भुगत रहे हैं। याद रहे कि हिंमत बिस्वा असम के 'स्वास्थ्य' व 'शिक्षा' मंत्री है। *(इंडियन एक्सप्रेस, 22 नवम्बर, 2017)*

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की माँग

एन टी पी सी ऊंचाहार दुर्घटना की निष्पक्ष जाँच हो, पीड़ितों को मिले समुचित मुआवजा

सीटू व अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की 4 नवम्बर, 2017 को नई दिल्ली में हुई संयुक्त बैठक में, उत्तरप्रदेश की ऊंचाहार एन टी पी सी परियोजना में 1 नवम्बर, 2017 को हुई बड़ी दुर्घटना पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की। इस दुर्घटना में 3 नवम्बर, 2017 तक 33 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी थी।

10 नवम्बर तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 पहुँच गयी और कई अन्य गंभीर स्थिति में उत्तरप्रदेश व दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हैं। ठेका मजदूरों समेत सैकड़ों मजदूर गंभीर रूप से धायल हुए हैं जिनमें से कई 70 प्रतिशत से अधिक जल गये हैं और जीवन के लिए संधर्ष कर रहे हैं।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने उस दिन जारी एक बयान में इस गंभीर दुर्धटना में मारे गये लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी हार्दिक संवेदनायें प्रकट कीं।

बयान में कहा गया कि मजदूरों के बयानों सहित विभिन्न रिपोर्ट बॉयलर फटने के पीछे अथारिटी की गंभीर लापरवाही की ओर संकेत करती हैं। ऐसी रिपोर्ट हैं जिनमें बायलर में खराबी की बात सामने आ चुकी थी और इसीलिए दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों की गंभीर कमी का भी पर्दाफाश हुआ है।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की माँग है कि :

- दुर्घटना के कारणों का पता लगाने तथा दोषी लोगों को सजा देने कि लिए निष्पक्ष एजेंसी से उच्च स्तरीय जाँच कराई जाये तथा ऐसी भयानक दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने के कदम सुनिश्चित किये जायें;
- एन टी पी सी घायल ठेका मजदूरों सहित सभी घायलों के पूरे ईलाज का खर्च उठाना सुनिश्चित करे;
- सभी मृत कर्मचारियों के परिवारों को कम से कम 50 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाये;
- गंभीर घायलों के लिए घोषित मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया जाये; और
- ठेका मजदूरों सहित मृतकों के आश्रितों को तथा गंभीर घायल होने से काम करने लायक न रह गये कर्मचारियों के आश्रितो को कंपनी में स्थायी रोजगार दिया जाये

प्रधानमंत्री की शाबासी पाने की दौड़ में

बिहार में नीतीश कुमार की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने में पूरी रफ्तार से लगी है तथा उसने खुले में शौच करने वालों (पुरूष या स्त्री) की तस्वीरें लेने का आदेश दिया है। 31 दिसम्बर, 2017 तक खुले में शौच से मुक्त घोषित होने की दौड़ में सरकार ने ऐसा करने के विशेष आदेश मुजफ्फरपुर व औरंगाबाद जिलों में शिक्षकों को दिये है। औरंगाबाद जिले में शिक्षकों ने इस कदम को मानवीय गरिमा के विरूद्ध बताते हुए इसका विरोध किया और मुद्दे को सामने लाने का काम किया। *(मीडिया रिपोर्टो से)*

किसानों का संघर्ष

संसद के सामने बैठी किसान संसद

184 किसान संगठनों के देश के सबसे बड़े मंच, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (ए आइ के एस सी सी) के बैनर तले देश के लगभग हर प्रदेश से आये हजारों किसानों ने 20–21 नवम्बर को राष्ट्रीय राजधानी में किसान मुक्ति संसद में भाग लिया। किसान मुक्ति संसद से पहले महीनों लम्बी किसान मुक्ति यात्रा निकाली गयी थी जिसमें लाभकारी मूल्य और कर्ज से मुक्ति के लिए अभियान में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा में 19 राज्यों में 500 से जयादा सभायें कीं गयीं।

20 नवम्बर को, किसानों का लाल, हरे, नीले, पीले व गुलाबी झंडो से सजा एक इन्द्रधनुषी जुलूस दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू हुआ जो कनाट प्लेस से होता हुआ संसद मार्ग पर पुलिस अवरोधकों के आगे किसानों के मुद्दों पर बैठी एक किसान संसद में बदल गया। अम्बेडकर भवन, गुरूद्वारा रकाबगंज व रेलवे स्टेशनों से भी हजारों किसान जुलूस बनाकर किसान संसद में पहुँचे। जुलूस व किसान संसद में अखिल भारतीय किसान सभा का जत्था सबसे बड़ा था।

रामलीला मैदान से शुरू हुए मार्च का नेतृत्व करने वाले नेताओं में ए आइ के एस नेतागण– अध्यक्ष अशोक धावले; उपाध्यक्ष अमराराम; सहसचिव वीजू कृष्णन, के के रागेश व बादल सरोज; वित्त सचिव पी. कृष्णाप्रसाद व अन्य राज्यों के नेता शामिल थे। अन्य नेताओं में ए आइ के एस सी सी के संयोजक वी एम सिंह; नर्मदा बचाओ ओदोलन की मेधा पाटकर; जय किसान आन्दोलन के योगेन्द्र यादव व अविक साहा; ए आइ के एम एस के राजाराम सिंह, प्रेम सिंह व कार्तिक राय; ए आइ के के एम एस के आशीष मित्तल व चन्द्रशेखर; स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी व अन्य नेता शामिल थे।

किसान संसद की शुरूआत मंदसौर व अन्य स्थानों पर हुई पुलिस गोलीबारी में शहीद हुए किसानों तथा आत्महत्या करने वाले किसानों तथा कीटनाषकों के जहर से यवतमाल में मारे गये किसानों को श्रृद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई।

किसान संसद के सामने दो विधेयक पेश किये गये–**कर्ज से किसानों की मुक्ति विधेयक, 2017** जिसे ए आइ के एस महासचिव व पूर्व सासंद हन्नान मोल्ला ने पेश किया तथा **कृषि उपज के लिए सुनिश्चित लाभकारी मूल्य का किसानों का अधिकार विधेयक, 2017** जिसे राजू शेट्टी, सांसद द्वारा पेश किया गया। इन विधेयकों पर सभी राज्यों में चर्चा की जायेगी, ड्रॉफटिंग कमेटी राज्यों का दौरा करेगी तथा जरूरी संशोघनों के बाद इन विधेयकों को लोक सभा व राज्य सभा में पेश किया जायेगा। सारे देश से संशोघन प्राप्त करने के बाद बिलों को हन्नान मोल्ला व राजू शेट्टी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा।

किसान संसद के सत्र के साथ ही 543 महिला किसान सदस्यों के साथ महिला किसान संसद भी बैठी जिसके उद्देश्यों को कविता कुरगंथी ने पेश किया व मेधा पाटकर ने संबोधित किया। संसद ने किसानों की दुर्दशा विशेषकर महिला किसानों की खराब स्थिति पर चर्चा की। किसान संसद में कर्ज के कारण आत्महत्या को मजबूर हुए कई किसानों की विधवायें, मातायें, बहनें व बेटियां भी शामिल थीं। इनमें से कुछ ने अपनी बदहाली के बारे में बताया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहादुरी के साथ सरकार की उन विनाशकारी नीतियों से लड़ने के संकल्प की घोषणा भी की जिनके चलते किसानों को आत्महत्यायें करनी पड़ीं। किसान संसद को एडवा की सुधा सुंदरमन व एन एफ आइ डब्लू की एनी राजा सहित महिला कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। महिला किसान संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों को किसान संसद में पेश किये जाने पर अपनी सहमति दी।

किसान संसद ने ए आइ के एस उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक अमराराम को राजस्थान के किसाान संधर्ष में ऐतिहासिक जीत के लिए और सासंद राजू शेट्टी को, नरेन्द्र मोदी नीत भाजपा सरकार द्वारा किसानों से वादाखिलाफी के विरोध में राजग को छोड़ देने के लिए सम्मानित किया।

संसद को संबोधित करते हुए डॉ. अशोक धावले ने भाजपा सरकार द्वारा किसानों के साथ किये गये विश्वासधात के बारे में बताया और उसे आजाद भारत की सबसे किसान विरोधी सरकार ठहराया। उन्होंने मुठठी भर कारपोरेटों को लाखों करोड़ की कर्ज माफी देने और करोड़ो संकटग्रस्त किसानों के लिए ऐसा करने से इनकार करने के लिए भाजपा सरकार की भर्त्सना की। उन्होंने यह भी कहा

कि न तो भाजपा और न ही काँग्रेस सरकारों ने केन्द्र में रहते, उत्पादन लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की डॉ. एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश को लागू किया। नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने तो ऐसा करने के अपने चुनावी वादे के साथ ही विश्वासधात किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की संधर्षशील एकता, जन–विरोधी सरकार की दमनकारी तिकड़मों और साम्प्रदायिक आधार पर लोगों को विभाजित करने के षडयंत्र, दोनों को परास्त करेगी। अमराराम और ए आइ के एस के महाराष्ट्र राज्य महासचिव अजित नावले ने क्रमशः राजस्थान व महाराष्ट्र में किसाान संधर्षो की जीत के बारे में बताया।

वी एम सिंह, योगेन्द्रयादव, अतुल अंजान, मेधा पाटकर, सुनीलम, प्रतिभा शिंदे, राजाराम सिंह, कोडिहल्ली चन्द्रशेखर, आशीष मित्तल, सत्यवान, अविक साहा, किरन बस्सा व अन्य किसान नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किसान संसद को संबोधित किया। सीटू अध्यक्ष व महासचिव व अन्य पदाधिकारियों समेत विभिन्न वर्गीय व जन संगठनों के नेता किसान संसद के प्रति एकजुटता व्यक्त करने गये।

किसान संसद ने भाजपा सरकार की किसान–विरोधी नीतियों के खिलाफ पेश दो विधेयको पर नवम्बर के आखिर में गुजरात से शुरू कर 26 नवम्बर के बीच दो महीने लम्बे देशव्यापी अभियान व जन सुनवाई का फैसला लिया है; इसके बाद राज्य स्तरीय कन्वेंशन किये जायेंगे; सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्ज में घिरे किसानों को बैंकों व निजी सूदखोरों द्वारा परेशान न किया जाये, स्थानीय स्तर पर संयुक्त प्रतिरोध खड़ा किया जायेगा।

उमर खान की हत्या

राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा किया

उम्मर के परिवार से मिलता ए आइ के एस प्रतिनिधिमंडल

ए आइ के एस अध्यक्ष डॉ. अशोक धावले के नेतृत्व में संगठन के अन्य नेताओं वीजू कृष्णन, पी कृष्णप्रसाद; राजस्थान किसान सभा के नेताओं छगन चौधरी, गुरचरण सिंह मोड, नत्थी लाल शर्मा, रैम्बो हवलदार व इमाम आसमौहम्मद के प्रतिनिधिमंडल ने 17 नवम्बर को राजस्थान के भरतपुर जिले के धटमिका गाँव के गरीब किसान व दिहाड़ी मजदूर उम्मर मौहम्मद खान के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की जिसकी 10 नवम्बर को राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों ने हत्या कर दी थी।

प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि उमर का परिवार और ज्यादातर मुसलमानों की आबादी वाला समूचा गांव ही पिछड़ा और गरीबी से धिरा हुआ है। गाय पालन और दूध का काम ही गांव वालों की गुजर–बसर का साधन है। चूंकि दूध कम दाम पर बिकता है, सारा गांव ही जैसे संकट का सामना कर रहा है। गायों की खरीद व बिक्री पर राजस्थानों में कानूनी पाबंदी नहीं है। गांव वाले जब घरों से गायें खरीदते–बेचते है तो इसके लिए रसीद की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में , गाय चोरी की बिना किसी शिकायत के, पीड़ितों के खिलाफ गाय तस्करी का मामला दर्ज करना पुलिस और प्रशासन की उन्हें दोषी मानने की पहले से तय मानसिकता का परिचायक है।

अलवर के डाक्टरों ने दावा किया कि उमर की मौत गोली लगने से नहीं हुई और शरीर में कोई गोली नहीं मिली। परिवार के सदस्यों व गांव वालों के आपत्ति जताने पर पुलिस को लाश को जयपुर भेजने पर मजबूर होना पड़ा जहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई !

उमर की हत्या गाहंकर गांव में हुई, वाहन गोविन्दगढ़ में मिला तथा लाश 15 किलोमीटर दूर रामगढ़ में रेल की पटरी पर मिली। यह सब दिखाता है कि दोषी अपराधियों ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए ऐसा किया जिससे लगे कि उसकी मौत दुर्घटनावश हुई। अलवर के डाक्टरों का व्यवहार भी शक के घेरे में है। मोदी के सत्ता में आने के बाद से अब तक साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा पीट–पीट कर 30 से ज्यादा लोगों को मारा जा चुका है। पहलू खान के मामले में भी असली अपराधियों को राजस्थान की भाजपा सरकार ने नहीं पकड़ा। पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया गया।

केन्द्र व राज्य सरकारें को तथा कथित गौरक्षकों की अवैध हरकतों पर लगाम लगाने के लिए तथा ऐसी हिंसा के पीड़ितों को समुचित मुआवजा देने के लिए जिला नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भाजपा की राज्य व केन्द्र सरकारों इन निर्देशों को लागू नही कर रही हैं।

प्रतिनिधिमंडल अलवर के एस पी व अन्य पुलिस अधिकारियों से भी मिला और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की। ए आइ के एस ने उम्मर के हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार किये जाने; उमर की हत्या की न्यायिक जाँच; उम्मर के परिवार को 1 करोड़ रूपये तथा घायलों में प्रत्येक को 25 लाख रूपये के मुआवजे; पशुओं के व्यापार को सरकार द्वारा सुनिश्चित किये जाने जाने; बाजार भाव पर अनुत्पादक पशुओं को खरीदने के लिए गाय रक्षा अधिनियम को संशोधित करने; तथा गौरक्षक जैसे गैर–कानूनी संगठनों पर पाबन्दी लगाये जाने की माँग की।

लाभकारी मूल्य की मांग करने वाले किसानों पर फिर से पुलिस की गोलीबारी

महाराष्ट्र के अहमदनगर में भाजपा सरकार की पुलिस ने 15 नवंबर को सैकड़ों गन्ना किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठी चार्ज किया और गोलीबारी करके 7 किसानों को गंभीर घायल कर दिया जिन्हे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है।

किसान गन्ने का लाभकारी मूल्य 3100 रुपये प्रति टन की दर पर और निजी मिल मालिकों से जमा बकाए के भुगतान की मांग कर रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान महाराष्ट्र के कई केन्द्रों में लाभकारी मूल्य के लिए गन्ना किसानों का आंदोलन चल रहा है। उसी दिन ए.आई.के.एस. के एक बयान में कहा गया है कि बीजेपी की राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया और अब आंदोलनरत किसानों पर पुलिस को छोड़ दिया है। ए.आई.के.एस. ने सभी घायल किसानों को जरूरी और पर्याप्त मुआवजे और चिकित्सा व्यय देने और उत्पादन लागत की डेढ़ गुना पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की मांग की है।

झारखंड में भूख से संतोषी की मौत

ए आइ के एस प्रतिनिधिमंडल ने सिमडेगा के कारीमाटी गांव का दौरा किया

वित्त सचिव पी. कृष्णाप्रसाद के नेतृत्व में ए आइ के एस के एक प्रतिनिधिमंडल ने किसान सभा नेताओं सुरजीत सिन्हा, प्रफुल्ल लिंडा, सुफल महतो व बिरेन्द्र कुमार के साथ 10 नवम्बर को झारखंड के सिमडेगा जिले के कारीमाटी गांव का दौरा किया जहाँ 28 सितम्बर को 11 वर्षीय संतोषी कुमारी की भूख से मौत हो गयी थी।

झारखंड में अब तक भुखमरी से 5 मौतों की खबरें आ चुकी है। भूख से मरे अन्य लोगों में धनबाद के बैधनाथ रवि दास, देवधर जिले के मोहनपुर के रूपलाल मुरमू,गढ़वा के सुरेश ओरांव व धनबाद जिले के कटरास के विनोद रवि दास शामिल हैं। इनमें से तीन आदिवासी थे। लेकिन झारखंड सरकार इससे इन्कार करती रही है तथा मामले की गंभीरता को दबाने की कोशिश कर रही है।

प्रतिनिधिमंडल संतोषी के परिवार के सदस्यों उसकी मां कोयिली देवी, दादी, बहन, चाचा व अन्य गांव वालों से मिला। परिवार के पास ठीक–ठाक मकान व स्थायी आमदनी नहीं है। उनके पास केवल 12 डेसीमल जमीन है। परिवार को एक महीने में 10/12 दिन का काम मिलता है तथा महिला को 100 रूपये व पुरूष को 150 रूपये वेतन मिलता है।

परिवार वालों ने बताया कि संतोषी की मौत भूख के कारण से हुई तथा उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बयान को कि मौत बीमारी से हुई, गलत बताया। कोयिली देवी के नाम का राशन कार्ड सं०. 202006991124 इस बात का साक्ष्य देता है कि परिवार को अप्रैल 2017 से राशन नहीं मिला था और लड़की की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार को 21 किलो चावल, 14 किलों गेहूँ व 2 लीटर मिट्टी का तेल डीलर अरूण शाह से 23 अक्टूबर, 2017 को मिला।

झारखंड में लगभग 2.5 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी हैं। अधिकारिक आंकड़ो के अनुसार 11.30 लाख कार्ड धारकों के नाम सूची से आधार से न जुड़े हाने के कारण से हटा दिये गये। मुख्य सचिव ने मार्च में सभी जिलों को निर्देश दिया था कि आधार से नहीं जुड़े राशन प्रणाली लाभार्थियों के नामों को काट दिया जाये। लगभग 385 गरीब आदिवासी, दलित व अल्पसंख्यकों के परिवारों को राशन कार्ड रद्द कर या नवीनीकरण न कर लाभ से वंचित कर दिया गया।

संतोषी कुमारी के परिवार के पास आधार कार्ड है और उनका राशन कार्ड डीलर के पास था। लेकिन परिवार को अप्रैल से राशन नहीं दिया गया था चूंकि बायोमेट्रिक डाटा उपलब्ध नहीं था। प्रशासन की ऐसी असफलता को लोगों को भोजन के अधिकार से वंचित करने के लिए कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है। यह दायित्व की एक आपराधिक कोताही है तथा लड़की की दुखद मौत के लिए सभी दोषियो पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिये।

ए आइ के एस ने झारखंड में भूख से मौतों की जाँच के लिए तथा जिम्मेदारी तय करने के लिए एक न्यायिक आयोग नियुक्त किये जाने; पीड़ित के परिवार के लिए सरकार द्वारा घर बना कर देने; 10 लाख रूपये मुआवजा तथा स्थायी रोजगार व पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित किये जाने कर मांग की है।

यह हिला देने वाला व अमानवीय है कि घटना के बाद गांव में आर एस एस– भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीड़ित के परिवार को लगातार उत्पीड़ित किया और उनपर राज्य सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। असुरक्षा की स्थिति में उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। यह सकारात्मक है कि स्थानीय प्रशासन ने परिवार को वापस आने के लिए मनाया और चार सुरक्षा गार्डो को सुरक्षा में लगाया।

राज्यों से

ओड़िशा

आशा मजदूरों का दिन-रात का धरना

भुवनेश्वर में सीटू की ओडिशा आशा कर्मी एसोसिएशन के बैनर तले, राज्य के विभिन्न हिस्सों से आने वाले 3000 आशा मजदूरों ने रेलवे स्टेशन से जुलूस निकाला और विधानसभा के सामने पहुंचने पर, जुझारु प्रदर्शन किया और 17 नवंबर को अनिश्चित कालीन राज्य स्तर का क्रमिक धरना शुरु किया जो 22 नवंबर को छटे दिन में प्रवेश कर गया। यूनियन अपने 20 सूत्रीय माँग पत्र को लेकर आंदोलन कर रही है जिसमें सरकार के कर्मचारियों के तौर पर नियमितकरण, न्यूनतम् वेतन के रूप में 18,000 रुपये और उस समय तक प्रोत्साहन की वृद्धि, पीएफ और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा, वेतन का नियमित भुगतान आदि शामिल हैं।

यूनियन के अध्यक्ष आर आर सारंगी, महासचिव नलिनी साहू और सीटू के राज्य के नेता लम्बोदर नायक, जनार्दन पति, बिष्णु मोहंती, दुसमन्ता दास, सत्यानंद बेहरा, रमेश जेना और अन्य ने बैठक को संबोधित किया। *(योगदान : रमेश जेना)*

बिहार

ट्रक मजदूरों और ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल

बिहार के ट्रक मजदूरों और ऑपरेटरों ने 15 नवंबर से राज्य के 38 जिलों में आवश्यक वस्तुओं सहित तमाम सामानों को ले जाने वाले ट्रकों के संचालन को पूरी तरह से रोककर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु कर दी और हजारों ट्रकों को सड़कों के किनारे खड़ा कर दिया। 17–19 नवम्बर के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हड़तालियों ने मशाल जुलूस निकाले।

ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (ए.आई.आर.टी.डब्ल्यू.एफ.) ने मांगों और हड़ताल का समर्थन किया और पूरे देश में अपने से सम्बद्ध यूनियनों को रैली निकालने और गेट बैठकों का आयोजन करके प्रदर्शनों के माध्यम से समर्थन और एकजुटता का इजहार करने के लिए कहा है।

हड़ताल का आह्वान् एआईआरटीडब्ल्यूएफ की बिहार इकाई और बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन द्वारा 8 सूत्रीय की माँगों के लिए संयुक्त रूप से किया। जिसमें राज्य सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2017 को अधिसूचित 'माइनर खनिज नियम' को वापस लेने की मांग प्रमुख रुप से की गई, जिसके तहत इस तरह के सामान को ले जाने के लिए ऑनलाइन जोड़ना अनिवार्य किया गया है। ऐसा करने में विफलता के मामले में कारावास सहित दंडनीय प्रावधान किया है; राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण, लाइसेंस जारी करने, परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा आदि के लिए बढ़ी हुई फीस और दंड की वापसी; और संसद के समक्ष लंबित मोटर वाहन संशोधन विधेयक, 2017 की वापसी आदि माँगें शामिल हैं। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने एक राज्य स्तर के धरना का आयोजन किया गया जिसमें 25 जिलों से आने वाले परिवहन मजदूर शामिल हुए, जिसका उद्घाटन सीटू बिहार राज्य के महासचिव गणेश शंकर सिंह ने किया और ए.आई.सी.सी.टी.यू. के राज्य महासचिव आर.एन. झा, पटना कोओर्डीनेशन कमेटी ऑफ यूनियन्स एण्ड एसोसिएशन्स के संयोजक मंजुल कुमार दास, निर्माण संघ के नेता नथून जामदार और कई परिवहन मजदूरों ने सम्बोधित किया।

हड़ताली मजदूरों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के ओएसडी से मुलाकात की और 8 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री के साथ बैठक की आश्वासन पर संयुक्त बैठक के एकमत से निर्णय के अनुसार अगले 10 दिनों के लिए हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। *(राज कुमार झा द्वारा)*

पंजाब

आँगनवाड़ी कर्मचारियों का राज्यव्यापी धरना

आई.सी.डी.एस. को समाप्त करने के सरकार के निर्णय को वापस लेने की माँग के लिए

रोपड में विधान सभा अध्यक्ष के समक्ष

अमृतसर

लुधियाना

फिलौर

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व–प्राथमिक कक्षाओं में 3–6 वर्ष आयु के बच्चों को शामिल करके इन बच्चों को आईसीडीएस योजना के लाभ से बाहर निकालने के लिए पंजाब सरकार के निर्णय को वापस लेने की माँग को लेकर, आंगनवाड़ी मूलाजिम यूनियन (सीटू) के आह्वान् पर, हजारों आंगनवाड़ी मजदूर और सहायकों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के कैबिनेट मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और सांसदों के आवासों पर अमृतसर, तरनतारन, दीनानगर, रोपड, खन्ना, लुधियाना, भटिंडा, पटियाला, नाभा, संगरूर, मोहाली, फिलौर और फतेहगढ़ साहिब में धरने आयोजित किए।इन धरनों को आंगनवाडी महासंघ कह अखिल भारतीय अध्यक्षा और सीटू की राष्ट्रीय सचिव उषा रानी, यूनियन की राज्य अध्यक्ष हरजीत कौर और महासचिव सुभाष रानी और सीटू के प्रदेश के महासचिव रघुनाथ सिंह सहित नेताओं ने सम्बोधित किया था।

केरल

रेलवे के निजीकरण के खिलाफ कन्वैन्शन

संयुक्त रेलवे कर्मचारी फोरम में रेलवे कर्मचारी संघों– डीआरईयू (सीटू), ए.आई.एल.आर.एस.ए. और ए.आई.एस.एम.ए.–ने रेलवे के निजीकरण और विशेष रूप से एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन के निजीकरण के विरुद्ध एरनाकुलम में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्घाटन सीटू के राज्य महासचिव ई. करीम ने किया था; डीआरईयू के सहायक महासचिव सुजोभानन ने दस्तावेज पेश किया और सीटू के राज्य सचिव के. एन. गोपीनाथ, कॉन्फडरेशन के रॉय, ए.आई.एल.आर.एस.ए. के एम.एम. रोली और ए.आई.एस.एम.ए. के टी. वीनू ने संबोधित किया। एन रविकुमार ने अध्यक्षता की।

ई.पी.एफ.ओ. के सी.बी.टी. की बैठक

'छूट प्राप्त इकाईयों के पेंशनरों' के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कार्यान्वयन पर

23 नवंबर को, पेंशनभोगियों के संगठनों ने नई दिल्ली में सीबीटी बैठक के बाहर प्रदर्शन का आयोजन किया था। सीबीटी में सीटू के प्रतिनिधि और इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ए के पद्मनाभन ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सीटू सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पूर्ण कार्यान्वयन की माँग कर रहा है और सीबीटी बैठक में इस मुद्दे को उठाना जारी रखेगा।

यहाँ तक कि सीबीटी की बैठक से पहले परिचालित एजेंडे पर चर्चा शुरू हो सकती है, यह तूफानी हो गया और मजदूर प्रतिनिधियों ने पिछले बैठक के फैसले के बावजूद, 'वृद्धि हुई पेशंन के मुद्दे' को एक अलग एजेंडा के रूप में अनदेखा करने के लिए ईपीएफओ की गंभीर आलोचना की। इसके बजाय ईपीएफओ ने एकतरफा रूप से 31 मई, 2017 को 'छूट प्राप्त इकाइयों के पेंशनरों' पर परिपत्र जारी किया, जिन्होंने पूरे वेतन पर योगदान दिया था, ने विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई की और इनकी कई याचिकाऐं विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। ईपीएफओ ने इन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए एक याचिका दायर की है।

चर्चा के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि छूट प्राप्त इकाईयों और संबंधित मुद्दों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सीबीटी की एक अलग बैठक दिसंबर के पूर्वार्द्ध में होगी। श्रम मंत्री ने इस मुद्दे पर दिसंबर में सीबीटी की बैठक के बाद पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलने का आश्वासन दिया।

लेखांकन

ईपीएफओ का 15% कोश ईटीएफ के माध्यम से बाजार में निवेश किया गया है। इसके बारे में लेखांकन व्यक्तिगत आधार पर है – 85% को रूपये में और 15% को इसके मौजूदा बाजार मूल्य के साथ इकाइयों के रूप में दिखाया गया है। अगस्त, 2015 से अक्टूबर 2017 की अवधि के दौरान ईपीएफओ ने औसत रिटर्न 21.87% के साथ ईटीएफ में 32,298.73 करोड़ रुपए का निवेश किया था। एसबीआई म्युचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड ने इन निवेशों का संचालन किया है। जो लोग ईपीएफ से अग्रिम लेते हैं, वे भी ईपीएफओ से अपने मौजूदा मूल्य पर इन यूनिटों को भुना सकते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण लंबित मुद्दे

सीटू द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को अभी भी लंबित रखा गया है जिनमें – (i) 11 मार्च 2015 को बैठक में पेंषन से पूर्ण वसूली के बाद प्रतिभूति (कम्यूटेशन) राशि की वसूली को रोकने का निर्णय लिया गया था, और इसे ईपीएफओ द्वारा केवल 17 अगस्त 2016 को श्रम विभाग को भेजा गया था, श्रम सचिव के साथ पिछली मीटिंग में उनके द्वारा बिना किसी देरी के इस पर गौर करने का आष्वासन के बावजूद, अभी भी सरकार के पास लंबित है। फिर भी, 'एजेंडे पेपर्स' में इसका कोई संदर्भ नहीं है। – (ii) अप्रैल 2017 की बैठक में ईडीएलआई लाभ को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह हाल ही की अवधि में सीबीटी द्वारा एकमात्र लाभकारी निर्णय है। निर्णय के तहत न्यूनतम् बीमा 2.5 लाख रुपये और एक लॉयल्टी भुगतान होना था। – (iii) पेंशनरों को ईएसआई से जुड़े चिकित्सा लाभ और वेतन की अधिकतम् सीमा बढ़ाना। – (iv) योजना कर्मचारियों के लिए पीएफ पर – (अ) रेलवे पोर्टर्स के लिए पीएफ पर; रेलवे का कहना है कि वे उसके मजदूर नहीं हैं; अन्याय को इंगित किया गया है और पुनर्विचार की मांग की गई थी।

23 नवंबर को बैठक, सीबीटी के लंबे समय तक एटक से रहे सदस्य कॉमरेड सचदेवा को श्रद्धांजलि से शुरू हुई। सीबीटी ने एटक के नए सदस्य, रामेंद्र कुमार, एटक के अध्यक्ष का स्वागत किया। बैठक की अध्यक्षता नए श्रम मंत्री ने की थी।

न्यूनतम मजदूरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बार–बार क्या कहा

1. **एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (प्राईवेट) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में, 1959 एससीआर 12** में संविधान खंडपीठ, ने कहा है कि ''हालांकि, यह याद रखना चाहिए कि उद्योग की भुगतान करने की क्षमता के बावजूद भी केवल न्यूनतम् या निर्वाह मजदूरी तय करनी ही होगी।''

2. **यू. यूनिचौई बनाम केरल राज्यएआईआर 1962 एससी 12** में संविधान खंडपीठ, ने कहा, *''अधिनियम (न्यूनतम् वेतन अधिनियम, 1948) ने यह अनुशंसा की है कि अनुसूचित उद्योगों में एक मजदूर व उसके परिवार के निर्वाह एवं रखरखाव और एक मजदूर के तौर पर अपनी दक्षता बनाए रखने के दोहरे उद्देश्य से न्यूनतम् वेतन की दर तय की जानी चाहिए।''*

3. **चंद्र भवन बोर्डिंग और लॉजिंग बनाम मैसूर राज्य (1969) 3 एससीसी 84** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, *''यह देखना राज्य का कर्तव्य है कि उस वेतन के भुगतान की उद्योग या यूनिट की क्षमता के बावजूद कर्मचारियों को कम से कम न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाऐ।'' ''और हम यह नहीं मानते हैं कि इस निर्धारित दर से उद्योग या एक छोटी इकाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि वे करते हैं, तो उद्योग या इकाई को मौजूद होने का कोई अधिकार नहीं है। व्यापार की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि शोषण करनी की स्वतंत्रता है।*

4. **कामारी मेटल्स एंड एलोयज बनाम वर्कमैन, एआईआर 1967 एससी 1175 में सुप्रीम कोर्ट की 3** न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, *''पहला सिद्धांत यह है कि न्यूनतम् मजदूरी है, मुनाफे की निरपेक्षता, संस्थान की वित्तीय स्थिति या कम वेतन पर मजदूरों की उपलब्धता के बावजूद भी उसका भुगतान किसी भी हालत में होना है। यह न्यूनतम् मजदूरी उद्योग के प्रकार से स्वतंत्र है और बड़े या छोटे सभी पर समान रुप से लागू होता है यह निम्नतम् सीमा निर्धारित करता है जिसके नीचे के वेतन को मानवता को डुबोने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ''*

5. **स्टैण्डर्ड वैक्यूम रिफाइनिंग कम्पनी (सुप्रा)** में उच्चतम् न्यायालय ने कहा *''. . . न्यूनतम् वेतन हमेशा और हर हालतों में। जो नियोक्ता न्यूनतम् वेतन का भुगतान नहीं कर सकता, उसे मजदूरों को काम पर रखने का अधिकार नही है और उद्योग चलाने की कोई न्यायसंगतता नहीं है।''*

6. **श्रमिक बनाम रेप्टाकोस ब्रेट्ट एण्ड कम्पनी लिमिटेड (1992) 1 एससीसी 290** में उच्चतम् न्यायालय ने न्यूनतम् वेतन निर्धारित करने के वास्ते मानक मानदण्ड तय करते हुए निम्नानुसार कहाः

   ''वर्ष 1957 में नई दिल्ली में आयोजित 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की त्रिपक्षीय कमेटी ने वेतन नीति की घोषणा की जिसका पालन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होना था। कमेटी ने 'न्यूनतम् वेतन' निर्धारण के वास्ते निम्नलिखित पाँच मानदण्डों को स्वीकार कियाः

   1) न्यूनतम् वेतन की गणना में एक कर्मचारी के लिए मानक श्रमिक वर्ग परिवार को 3 उपभोग इकाइयों को शामिल किया जाना चाहिए; महिलाओं, बच्चों और किशोरों की कमाई को छोड़ देना चाहिए।

   2) न्यूनतम् खाद्य आवश्यकता को कैलोरी के शुद्ध सेवन के आधार पर गणना की जानी चाहिए, जैसा कि एक औसत गतिविधि के औसत भारतीय वयस्क के लिए डा० आकॉयड द्वारा सुझाया गया है।

   3) कपड़ों की आवश्यकताओं का आकलन प्रति व्यक्ति 18 गज प्रति वर्श की खपत के अनुसार होना चाहिए जो औसत श्रमिक परिवार के चार सदस्यों के लिए कुल 72 गज।

4) आवास के संबंध में, सरकार की औद्योगिक आवास योजना के तहत प्रदान किए गए न्यूनतम क्षेत्र से संबंधित किराए को न्यूनतम वेतन तय करने में विचार किया जाना चाहिए।

5) ईंधन, प्रकाश और अन्य 'विविध' व्ययों की मदों के लिए कुल न्यूनतम मजदूरी का 20% अतिरिक्त रुप से जोड़ा जाना चाहिए।''

''स्टैण्डर्ड वैक्यूम रिफाइनिंग कम्पनी (सुप्रा) के मामले में इस अदालत ने अनुमोदन के साथ उपरोक्त मानदंडों को संदर्भित किया है। 'न्यूनतम्वेतन' की अवधारणा अब वैसी नहीं है, जैसी कि 1936 में थी। यहां तक कि 1957 भी पीछे छूट गया है। एक मजदूर का वेतन अब एक नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक अनुबंध नहीं है। इसमें श्रम कानूनों के तहत सामूहिक सौदेबाजी की ताकत है। वेतन की प्रत्येक संरचना को सामाजिक न्याय के परिपेक्ष्य में जांचना होगा, जो कि आज के समाज का जीवंत आधार है।

''वेतन संरचना के सामाजिक–आर्थिक पहलू को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह दृढ़ मान्यता है कि उद्योगों में न्यूनतम् वेतन तय करने के लिए एक दिशा–निर्देशन के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त घटक जोड़ा जाना आवश्यक हैः –

4) बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकताऐं, त्योहारों/समारोहों सहित न्यूनतम् मनोरंजन और बुढ़ापे, विवाह आदि के प्रावधानों को कुल न्यूनतम मजदूरी का 25% अतिरिक्त रुप से जोड़ा जाना चाहिए।''

वेतन संरचना, जो लगभग ऊपर के छह घटकों के आधार पर तय होती है, वह केवल निर्वाह स्तर पर न्यूनतम् वेतन से ज्यादा कुछ नहीं है। कर्मचारी हर समय और सभी परिस्थितियों में न्यूनतम् मजदूरी के हकदार हैं। एक नियोक्ता जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर सकता है उसे मजदूरों को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है और उद्योग चलाने का कोई औचित्य नहीं है।''

मूल्य वृद्धि का कीर्तिमान

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा नवम्बर 2017 में जारी किए गए आँकड़ों के अनुसार अक्टूबर माह में हुई मूल्य वृद्धि निम्न प्रकार हैः

- थोक मूल्य सूचकांक में 3.59% की वृद्धि हुई;
- खाद्य मूल्यों में 4.3% की वृद्धि हुई;
- सब्जी के मूल्यों में समग्र रुप से 36.61% की वृद्धि हुई;
- प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, मांस और मछली 5.76% महंगे हो गऐ;
- धान में 3.10% की बढ़ोतरी हुई;
- ईंधन और बिजली की कीमतों में 10.52% की वृद्धि हुई – 12.87% तक पेट्रोल; एलपीजी 26.53%;
- कपड़े और जूते 4.76% ऊपर गये;
- विनिर्मित उत्पादों, जो इंडेक्स में लगभग 64.23% शामिल हैं, की कीमतों में 2.62ः वृद्धि दर्ज की गयी;
- आवास महंगाई दर 6.7% रही।

30 अक्टूबर

देशव्यापी जन एकता मशाल मार्च आयोजित

विभिन्न वर्गों, जन समूहों और सामाजिक संगठनों और आंदोलनों के सबसे बड़े मंच, जन एकता जन अधिकार आंदोलन (जे.ई.जे.ए.ए.) के 18 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन से किए गए आह्वान् के जवाब में; लोगों ने देश के लोकतांत्रिक ढ़ाँचे, धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने और जन–अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ 30 अक्टूबर को जन एकता मशाल (एकता की लौ) के माध्यम से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सैकड़ों लोग विभिन्न स्थानों पर एकत्र हुए। सीटू केंद्र में निम्नलिखित कुछ रिपोर्टें मिलीः

दिल्लीः सीटू, एटक, ए.आई.सी.सी.टी.यू., ए.आई.यू.टी.यू.सी., यू.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी., एस.एफ.आई., डी.वाई.एफ.आई., ए.आई.डी.डब्ल्यू.ए. सहित विभिन्न वर्गों एवं जन–संगठनों और आंदोलनों के 300 से ज्यादा सदस्यों ने शहीदी पार्क से सांय 5 बजे मशाल जुलूस निकाला जो आई.टी.ओ. पर बड़ी रैली में बदल गया। यह मशाल जुलूस जन–एकता, जन–अधिकारों और जन–विरोध की रक्षा में; मोदी सरकार की जन–विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता के विभिन्न वर्गों में बढ़ते संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त करने; सांप्रदायिक ताकतों को अलग–थलग करने की शपथ लेने; और नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ एकजुट होने के लिए आयोजित किया गया। 'एकता की लौ' के रूप में मोमबत्तियां जलाई गयी; मजदूरों और किसानों के बढ़ते संघर्षों के समर्थन में तथा नोटबन्दी, जीएसटी और 'रोजगार विनाशक' अर्थव्यवस्था के खिलाफ नारे लगाऐ गए। जन बैठक की अध्यक्षता सीटू के राज्य अध्यक्ष वीरेन्द्र गौड ने की और सीटू की राष्ट्रीय नेता ए आर सिंधु और ए.आई.सी.सी.टी.यू. के संतोश रॉय और अन्य ने संबोधित किया।

ओडिशाः जे.ए.जे.ए.ए. ओडिशा ने राज्य की राजधानी भुवनेश्वर और कटक, राउरकेला, जगतसिंगपुर, बालासोर, पुरी तथा अंगुल आदि जिला मुख्यालयों और औद्योगिक केंद्रों में मशाल जुलूसों के आयोजन किए। भुवनेश्वर में राजमाहल चौक से शुरु हुए मशाल जुलूस में विभिन्न जन संगठनों के सैकड़ों सदस्य शामिल हुए, आरएसएस की अगुवाई वाली मोदी सरकार की लोक–विरोधी नीतियों के खिलाफ और जे.ए.जे.ए.ए. के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाऐ गऐ 26 सूत्रीय जनता के माँग पत्र के समर्थन में नारे लगाए गए। जुलूस राम मंदिर चौक पर एक रैली में बदल गया, जिसे ए.आई.के.एस. के महासचिव हन्नान मुल्ला और संयुक्त सचिव विजू कृष्णन, ओडिशा कृषक सभा के सचिव सुरेश पाणिग्रही, ओडिशा कृषक सभा के अध्यक्ष याम्बेष्वर सामंतराय, अग्रगामी किसान सभा के ज्योति महापात्रा; सीटू के अलीकिशोर पटनायक और दुस्मंत दास, एटक के रामकृष्ण पांडा, ए.आई.सी.सी.टी.यू. के महेंद्र परिंदा, ए.आई.यू.टी.यू.सी. के जयसेन मेहर; एडवा की तापसी प्रहाराज; डी.वाई.एफ.आई. के जतिन मोहंती; आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के साला मरांडी और कई संगठनों के नेतृत्वकारी प्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया।

केरलः जे.ए.जे.ए.ए. के अखिल भारतीय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, सभी वर्गों के जन–संगठनों और आन्दोलनों की एक राज्य स्तरीय बैठक 12 अक्टूबर को आयोजित की गयी। तदनुसार, जे.ए.जे.ए.ए. के प्रस्तावों और मांगों को स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। 30 अक्टूबर को मोमबत्ती की रोशनी को 'एकता की लौ' के रूप में निकाला गया और राज्य भर में सभी जिला मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों पर जन बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में तीन नारों 'जन–एकता', 'जन–अधिकार' और जन–प्रतिरोध' का उल्लेख किया गया। मुख्य आकर्षण, 'एकता की लौ' थी जिसने लोगों और मीडिया को व्यापक रूप से आकर्षित किया था।

उत्तर प्रदेशः नगरपालिका चुनाव और राज्य भर में धारा 144 लागू होने, व्यापक पैमाने पर फसलों की कटाई और अन्य राजनीतिक संगठनात्मक प्राथमिकताओं के बावजूद बुलंदशहर, इटावा, आगरा, चंदौली, देवरिया, वाराणसी, एटा, कासगंज, बिजनौर, कुशीनगर,

गोरखपुर, लखनऊ, गाजीपुर, हरदोई, बरेली, बलिया, कानपुर और बस्ती के जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस, प्रदर्शन और आम बैठकें आयोजित की गयी। जे.ए.जे.ए.ए. के राष्ट्रीय सम्मेलन में पारित 26 सूत्रीय मांगों और संकल्प को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया और इन पर ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री को भेजे गए।

हरियाणाः 30 अक्टूबर को गुड़गांव में, विभिन्न वर्ग, जन और सामाजिक संगठनों और सीटू, एटक, ए.आई.यू.टी.यू.सी., एडवा, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति सहित और अन्य जन आंदोलनों ने स्थानीय कमला नेहरू पार्क में आयोजित जन बैठक में मशाल जुलूस की शुरूआत की और 6 बजे से महावीर चौक पर प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया जिसे सतवीर सिंह, अनिल पंवार, उषा सरोहा, हरदीप पुनिया और ईश्वर नास्तिक सहित जन–संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया। बैठक में 9–11 नवंबर को मजदूरों के महापडाव और 20 नवंबर की किसान रैली का समर्थन करते हुए और उन्हे सफल बनाने का आह्वान् किया गया।

मित्रों का पूँजीवादः कॉरपोरेट कर्ज बकाएदारों के लिए आम माफी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपये की भारी राशि से पुर्नपूँजीकरण करने का केंद्र सरकार का फैसले एक ऐसे समय पर आया है जब बैंकों पर भारी गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का बोझ पड़ा है। ब्याज सहित 11.5 लाख करोड़ रुपये के एनपीए के भुगतान के लिए बकाऐदार कॉरपोरेट्स् का पीछा करने के बजाय सरकार ने कर्ज बकाएदारों को असल में माफ कर दिया है।

बीजेपी सरकार ने 3 वर्षों के शासन के दौरान, 2 लाख करोड़ रुपए के कॉरपोरेट कर्जों को माफ किया है। कॉरपोरेटस् के लिए इस मेगा रियायत को अब इस पुनर्पूंजीकरण के सार्वजनिक वित्त पोशण के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। यह कॉरपोरेटों द्वारा लूटे गऐ बैंकों को, भारत की जनता की कीमत पर जमानत देने के समान है।

दोस्ताना पूंजीवाद की इससे बुरी कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। जबकि कृषि संकट के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के लिए ऋण माफी अस्वीकार कर दी गयी है, जबकि करोड़ों भारतीयों द्वारा बैंकों में जमा किए गए धन से लिऐ गऐ कर्जों को लेकर भाग जाने के लिए कॉर्पोरेट्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वित्त मंत्री का यह तर्क कि यह पुनर्पूंजीकरण बैंकों को कंपनियों को अधिक ऋण देने की अनुमति देगा, जो उच्च निवेष की ओर ले जाएगा, जो बदले में, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा; पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। निवेषों में वृद्धि, रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं कर सकती है। सिकुड़ते व्यापार की दुनिया में, भारतीय निर्यात 20 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है और भारत की जनता की क्रय शक्ति में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है, उस पर नोटबन्दी और और जीएसटी के कारण, घरेलू मांग में भारी कमी आई है।

यह सरकार अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी की परेशानी के मद्देनजर, विदेशी और देशी कंपनियों के पक्ष में नव–उदारवादी आर्थिक सुधारों का पीछा करना शुरू कर दिया है जो हमारी जनता के विशाल बहुमत पर और भी अधिक बोझ डालेगा। {सीपीआई (एम) पॉलिट ब्यूरो के बयान से}

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdkd vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,ulhihvkb

jkT;	dsn	vxLr 2017	fLkrEcj 2017
vk/k izns'k	xq.Vwj	279	277
	gSnjkckn	249	249
	fo'kk[kkiÿkue	285	282
	okjaxy	289	288
vle	MeMek frulf[k;k	262	267
	xokgkVh	249	250
	ycd flYpj	262	261
	efj;kuh tkjgkV	245	248
	jxkikjk rtiqj	243	243
fcgkj	eq?kj&tekyiqj	300	300
p.Mhx<	p.Mhx<	284	284
NÿhlxZ<	fHkykbZ	312	318
fnYyh	fnYyh	264	263
Xkkvk	xkvk	297	297
Xkqtjkr	vgenkckn	274	272
	Hkkouxj	270	272
	jktdkV	272	274
	lwjr	262	263
	oMknjk	262	260
gfj;k.kk	Qjhnkckn	263	276
	;euk uxj	277	258
fgekpy	fgekpy çn'k	259	264
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	262	279
>kj[k.M	ckdkjk	306	303
	fxfjMhg	335	332
	te'kniqj	308	309
	>fj;k	326	326
	dkMek	325	326
	jkph gfV;k	292	294
dukVd	cyxke	291	288
	cxykj	305	304
	gcyh /kkjokM	303	304
	ejdjk	299	297
	eSlwj	292	295
dsjy	,.kkdqye@vyoZ	299	303
	eq.MkD;ke	327	323
	fDoyku	282	280
e/; çn'k	Hkksiky	293	292
	fNUnokM+k	261	259
	bUnkSj	281	282
	tcyiqj		
egjk"V	eEcbZ	294	293
	ukxiqj	318	318
	ukfld	294	295
	iq.kk	277	276
	'kksykiqj	296	295
mMhlk	vkxx&rkypj	300	300
	jkmjdqyk	304	305
ikfMpfj	ikfMpfj	298	298
iatkc	verlj	287	286
	tkyU/kj	287	286
	yf/k;kuk	277	276
jktLFkku	vtesj	265	263
	HkhyokM+k	279	279
	t;iqj	275	274
rfeyukM	pUuS	263	276
	dk;EcVwj	271	270
	dUuwj	281	281
	enqjkbZ	282	281
	lqye	274	270
	fr#fpjkiYyh	289	285
f=iqjk	f=iqjk	295	293
mÿkj çn'k	vkxjk	257	254
	xkft;kckn	312	264
	dkuiqj	280	301
	y[kuÅ	293	291
	okjk.klh	281	277
if'pe cxky	vklulky	286	282
	nkftfyx	306	307
	nxkiqj	256	256
	gfYn;k	308	312
	gkoM+k	315	312
	tkyikbZxqM+h	272	270
	dkydkrk	279	279
	jkuhxat	270	270
	flyhxqM+h	257	254
vf[ky Hkkjrh; lpdkd		264	269
		285	285

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568;
  आइएफसीकोड : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्क:** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ
  प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन,
  13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; ईमेल: citubtr@gmail.com
  फोन: (011) 23221306 फैक्स: (011) 23221284

जन एकता अधिकार आंदोलन

30 अक्टूबर के जनएकता मशाल मार्च में सीटू की भागीदारी

(रिपोर्ट पृ० 24)

कन्नूर, केरल

एरनाकुलम, केरल

दिल्ली

गुड़गाँव, हरियाणा

राऊरकेला, ओडिशा

भुवनेश्वर, ओडिशा

बलिया, उत्तरप्रदेश

औरंगाबाद, महाराष्ट्र

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/15-17 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2015-2017 (Date of Publication - 5/12/2017)

किसान संघर्ष

नई दिल्ली; 20–21 नवम्बर, 2017

(रिपोर्ट पृ० 15)

विशाल जुलूस

संसद मार्ग पर आयोजित किसान संसद

एकता मंच पर उपस्थित नेतागण

उन किसानों के परिवार, जिन्होंने आत्महत्या की

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com)

सम्पादक : **के हेमलता**

असम

गुजरात

(Repor

पंजाब

महाराष्ट्र

रायकोट, पंजाब

महाराष्ट्र

कोलकाता

नोएडा (एन सी आर)

अमृतसर, पंजाब

नई दिल्ली

गुवाहाटी, असम

रोपड़ , पंजाब